प्रतिदिन

नीति आयोग की बैठक

आयोग की संचालन परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो कुछ कहा, देश चाहेगा वह वाकई साकार हो. उन्होंने कहा कि बीते वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और अब चुनौती इस वृद्धि दर को दहाई अंक में ले जाने की है. इसके साथ उन्होंने कहा कि वर्ष, 2022 तक न्यू इंडिया का सपना अब हमारे देश के लोगों का एक संकल्प है. नीति आयोग ऐसा मंच है, जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्रियों यानी केंद्र और राज्यों को देश के विकास के लिए एक टीम के रूप में काम करने के लिये की गई है. प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका अर्थ यही है कि हमें यदि दहाई अंक का विकास दर हासिल करना है और न्यू इंडिया के लक्ष्य को हासिल करना है तो सबको मिलकर काम करना होगा. यानी पूरा देश इसे अपना लक्ष्य माने. यह कैसे हो सकता है?

केवल दहाई अंक हासिल करने से ही न्यू इंडिया का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता. प्रधानमंत्री के अनुसार किसानों की आय को दोगुना करना, विकास की आस में बैठे जिलों का विकास, आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष, पोषण मिशन, स्वच्छता मिशन, कौशल विकास..आदि को साकार कर दिया जाए तो ही न्यू इंडिया का सपना साकार हो सकता है. उन्होंने कहा भी कि संचालन परिषद ऐसा मंच है, जो ₹ऐतिहासिक बदलाव' ला सकता है. उनकी बातों से किसी की असहमति नहीं हो सकती है. किंतु क्या देश का राजनीतिक वातावरण ऐसा है, जिसमें वाकई सारे राज्य एवं केंद्र एक टीम के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर इन लक्ष्यों के लिए काम कर सके? हालांकि प्रधानमंत्री ने यह जरूर कहा कि संचालन परिषद ने राजकाज से जुड़े जटिल मुद्दों को टीम इंडिया के रुप में सहयोगपूर्ण, प्रतिस्पधार्पूर्ण संघवाद की भावना के साथ लिया है लेकिन हमारे देश का पूरा सच यह नहीं है. चुनावी राजनीति ने ऐसा वातावरण बना दिया है, जहां विकास एवं सुरक्षा तक के मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन पाती. ज्यादातर राज्य अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार केंद्र की नीतियों को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं. मसलन आयुष्मान योजना को कई राज्यों ने स्वीकार नहीं किया. फसल बीमा योजना को कई राज्यों ने खारिज कर दिया. वास्तव में जब तक देशहित को ध्यान में रखते हुए केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग नहीं होगा तो फिर न्यू इंडिया का लक्ष्य पाना संभव नहीं होगा.

केजरीवाल के धरने के बीच

किसकी है दिल्ली?

मोदी सरकार द्वारा नियुक्तउपराज्यपाल निर्वाचित सरकार को अपने आधीन मानकर चलते रहे हैं. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि केंद्र द्वारा नियुक्त किया गया उपराज्यपाल या राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित सरकार से ऊपर नहीं हो सकता है. आने वाले दिनों में यह आवाज तेज हो सकती है. मोदी सरकार क्या जनतंत्र की एक और कसौटी पर फेल होना झेल सकती है?

अपने वादे पूरे करने में मौजूदा शासन की विफलताओं की पृष्ठभूमि में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच बढ़ती दूरी और 2019 के पूर्वार्ध में प्रस्तावित आम चुनाव को नजदीक आता देखकर विपक्ष की बढ़ती एकजुटता को देखते हुए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि इस बार की नीति आयोग की बैठक में सरकार को तीखे सवालों का सामना करना पड़ सकता है. फिर भी दिल्ली सरकार पर जिस तरह का राजनीतिक टकराव थोपा गया है, उसने केंद्र-राज्य संबंधों विशेषकर निर्वाचित सरकार के अधिकारों के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है.

बेशक, इसका अंदाजा तो आसानी से लगाया जा सकता था कि नीति आयोग की संचालन समिति की बैठक इस बार हंगामी होगी. फिर भी, किसी ने नहीं सोचा था कि इस चौथी बैठक पर, जिसमें केंद्र तथा सभी राज्यों के शीर्ष प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, केंद्र-राज्य संबंधों का मुद्दा छा जाएगा. लेकिन, ठीक ऐसा ही हुआ. और यह हुआ है दिल्ली में चल रहे राजनीतिक संकट के कारण.

यही नहीं, उससे भी बढ़कर दिल्ली सरकार के पक्ष खड़े होने के आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तथा प. बंगाल के मुख्यमंत्रियों के फैसले से. इसने सत्तर और अस्सी के दशकों के उस दौर की याद ताजा कर दी जब ज्योति बसु की अगुआई में विपक्षी मुख्यमंत्रियों के कई सम्मेलन हुए थे. केंद्र के बरक्स राज्यों के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा जनतंत्र की रक्षा के संघर्ष के एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर सामने था.

बेशक, अपने वादे पूरे करने में मौजूदा शासन की विफलताओं की पृष्ठभूमि में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच बढ़ती दूरी और 2019 के पूर्वार्ध में प्रस्तावित आम चुनाव को नजदीक आता देखकर विपक्ष की बढ़ती एकजुटता को देखते हुए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि इस बैठक में सरकार को तीखे सवालों का सामना करना पड़ सकता है. फिर भी दिल्ली सरकार पर जिस तरह का राजनीतिक टकराव थोपा गया है, उसने केंद्र-राज्य संबंधों विशेषकर निर्वाचित सरकार के अधिकारों के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है. विपक्ष को मौजूदा सरकार के खिलाफ कुछ और गोला-बारूद और विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए सीमेंट दे दिया है.

बेशक, इन चार सालों में नव-उदारवादी नीतियों के बुलडोजर तले राज्यों के अधिकारों को और खोखला किए जाने के सिलसिले को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया गया है. सबसे बड़ा सबूत है, राज्यों के कराधान के अधिकार को ही खत्म करने वाली जीएसटी व्यवस्था का लागू किया जाना. ऊपर से मौजूदा सरकार ने न सिर्फ राज्यपाल के पदों पर निरपवाद रूप से घोषित भाजपाइयों-संघ परिवारियों को बैठाया है, जिसने राज्यपाल के पदों पर राजनीतिक उद्देश्य से नियुक्तियों के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, बल्कि ₹अपने' राज्यपालों का इस्तेमाल कर दलबदल के जरिए न सिर्फ अनैतिक बल्कि अवैध तरीके से मेघालय तथा उत्तराखंड में ₹अपनी' सरकारें भी थोपीं, जिनके खिलाफ बाद में उच्च न्यायालयों को हस्तक्षेप करना पड़ा.

इसके अलावा ₹अपने' राज्यपालों की मदद से बहुमत न होते हुए भी गोवा, मणिपुर आदि में और एकदम हाल में कर्नाटक में ₹अपनी' सरकारें बैठाई, वह अलग. लेकिन, इस सब पर उठे सारे विरोध के बावजूद मौजूदा सरकार के चार साल के शासन में पहली बार है जब इतने धारदार तरीके से केंद्र सरकार द्वारा एक राज्य के अधिकारों के अतिक्रमण का मुद्दा उठा है और कम से कम पांच मुख्यमंत्रियों ने इसे ₹जनतंत्र पर हमला' करार दिया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अपने सहयोगी दो अन्य मंत्रियों के साथ एक हफ्ते से लगातार दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय में धरने पर बैठे होने चलते नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं ले पाए. इसकी विडंबना खुद ब खुद जाहिर है कि दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री को केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए उपराज्यपाल से मुलाकात का समय लेने के लिए उसके कार्यालय में हफ्ते भर धरना देना पड़ा है.

यह भी कम विडंबनापूर्ण नहीं है कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार की उपराज्यपाल से मुख्य मांग यही है कि वह दिल्ली में कार्यरत वरिष्ठ नौकरशाहों की चार महीने से जारी हड़ताल या निर्वाचित सरकार के बायकॉट को खत्म कराएं. याद रहे कि इसी साल फरवरी के महीने में मुख्यमंत्री निवास पर एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ कथित बदसलूकी की घटना, जिसका मामला अदालत में विचाराधीन है, के बाद से अधिकारियों ने मंत्रियों की बैठकों में आने से लेकर मंत्रियों के साथ फील्ड में जाने तथा मंत्रियों के फोन उठाने तक से पूर्ण असहयोग कर रखा है. इन अधिकारियों की नियुक्ति, तैनाती, तबादले, पदोन्नति के अधिकार, केंद्र के प्रतिनिधि के नाते चूंकि उपराज्यपाल के पास हैं, इस बहिष्कार को खत्म कराने में उसकी भूमिका केंद्रीय हो जाती है.

अगर दिल्ली की निर्वाचित सरकार का वरिष्ठ नौकराहों द्वारा यह बहिष्कार, जो अपने आप में भारतीय नौकराही के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है, पूरे चार महीने से जारी है और उपराज्यपाल इसके लिए अधिकार संपन्न होने के बावजूद इस संकट को खत्म कराने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, तो यह केंद्र सरकार प्रत्यक्ष इशारे के बिना संभव नहीं है.

खबरों का तो कहना यह भी है कि नीति आयोग की संचालन समिति की बैठक की पूर्वसंध्या में चंद्रबाबू नायडू, कुमारस्वामी, ममता बनर्जी तथा पिनरायी विजयन ने उपराज्यपाल के दफ्तर में धरने पर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जब लिखित रूप से इजाजत मांगी तो केंद्र के इशारे पर उपराज्यपाल ने उनके अनुरोध को ठुकराया था. खैर, इतना तय है कि दिल्ली के नौकरशाह यह अभूतपूर्व आंदोलन इसी से आभस्त होकर चलाए जा रहे हैं कि अपनी सेवा शर्तों का इस तरह खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करने की उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, उल्टे इसके लिए नियोक्ता के नाते केंद्र सरकार उन्हें पुरस्कृत भी कर सकती है.

संयोग नहीं है कि उपराज्यपाल नाम की संस्था शुरू से ही मौजूदा दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने में लगी रही है. इस बीच इस पद पर बैठे व्यक्ति तो बदले हैं, पर इस पद की भूमिका नहीं बदली है. किसी न किसी रूप में उपराज्यपाल निर्वाचित आप सरकार के प्रति केंद्र सरकार की शत्रुता का ही हथियार बना रहा है. जाहिर है कि दिल्ली के मामले में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इस तरह की समस्या, निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों, उनकी सीमाओं के संबंध में बनी अस्पष्टता से और बढ़ जाती है.

संयोग नहीं है कि मोदी सरकार द्वारा नियुक्तउपराज्यपाल निर्वाचित सरकार को अपने आधीन मानकर चलते रहे हैं. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि केंद्र द्वारा नियुक्त किया गया उपराज्यपाल या राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित सरकार से ऊपर नहीं हो सकता है. आने वाले दिनों में यह आवाज तेज हो सकती है. मोदी सरकार क्या जनतंत्र की एक और कसौटी पर फेल होना झेल सकती है? **रवी यादव.**

इंटरनेशनल मीडिया

भारत-नेपाल उड़ानों की रफ्तार

भारत-नेपाल के बीच वायु सेवा के चार नए द्वार खोलने का समझौता सुखद व स्वागतयोग्य है. ये चार नए वायु मार्ग काठमांडू बिराटनगर- ढाका, काठमांडू जनकपुर-पटना, काठमांडू जनकपुर-कोलकाता और काठमांडू महेंद्रनगर-दिल्ली के खुल जाने के बाद दोनों ओर के यात्रियों को खासी सहूलियत तो होगी ही, सिमरा हवाई अड्डे पर यातायात का भारी दबाव भी कम होगा. दो अन्य हवाई मार्गों पर भी बात चल रही है, जिस पर सितम्बर में फैसला हो जाने की उम्मीद है. निश्चित रूप से यह समझौता हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यह और पहले किया जा सकता था. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 में पहली नेपाल यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर सहमति बनी थी, लेकिन फैसला होने में चार साल का वक्त बीत गया. संयुक्त बयान में कहा गया था कि ये सीधी उड़ानें शुरू हो जाने के बाद पोखरा और भैरहवा के बीच वायु सेवा और आसान हो जाएगी और यात्रियों के पैसे की भी बचत होगी. इससे भारत-नेपाल के बीच वायु संपर्क तो बढेगा ही, नेपाल के समग्र अंतरराष्ट्रीय यातायात पर भी इसका खासा असर पड़ेगा. लेकिन यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि नेपाल के अन्य तमाम राजनयिक उपक्रमों की तरह इस मामले में भी काफी लेटलतीफी हुई है. 2014 में कई अन्य मुद्दों पर भी सहमति बनी थी, पर उनका सही तरीके से फॉलोअप नहीं हुआ और कई योजनाएं अटकी हुई हैं. इसके कई कारण रहे.

THE KATHMANDU POST

फरवरी, 2017 में दोनों देश इस मामले में शुरूआत के लिए एक तकनीकी टीम बनाने पर सहमत हुए थे, पर इसमें भी हीला-हवाली होती रही. इस बीच नए वायु मार्गों पर उड़ान की जरूरत लगातार महसूस होती रही है, क्योंकि नेपाल में दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे निमार्णाधीन हैं और एक अन्य पर काम चल रहा है. भैरहवा में 2019 तक और पोखरा में 2021 तक नया हवाई अड्डा चालू हो जाने की उम्मीद है. कहना न होगा कि इनमें से किसी भी हवाई अड्डे की वित्तीय या तकनीकी सफलता इन नई उड़ानों के बिना संभव नहीं होगी. उम्मीद है सितम्बर की बैठकें इसे गति देने वाली साबित होंगी.

काठमांडू पोस्ट, नेपाल.

प्रतिदिन

अध्ययन का तरीका

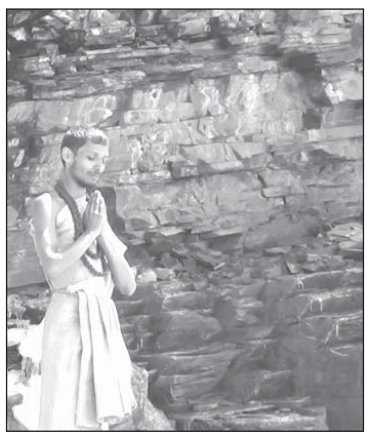

महर्षि रैक्य ने अपने पुत्र यवकीर्ति को ज्ञान की गरिमा का महत्व समझाया. वह इस बात से पूर्ण आश्वस्त भी हो गया कि सद्ज्ञान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है. फिर भी उसके मन में यह भ्रम बना रहा कि मनोयोगपूर्वक अध्ययन से ही ज्ञान की उपलब्धि संभव है. वह चाहता था कि इसका कोई सरल मार्ग मिल जाए. उसने सोचा कि तप करने से जब बहुत सिद्धियां मिल सकती है, तो साधना द्वारा ही उसे क्यों न प्राप्त कर लिया जाए. लंबे समय तक पढ़ने रहने का झंझट क्यों उठाया जाए. वह तपस्या करने लगा. पिता ने उसे समझाया कि ज्ञानार्जन भी तप ही है, लेकिन पिता का बात पुत्र की समझ में नहीं आयी.

यवकीर्ति स्नान के लिए नदी के जिस घाट पर जाया करता था, उस पर एक वृद्ध ब्राम्हण भी आने लगे. वह मुट्ठी भर-भर कर पानी में रेत डालते रहे. यवकीर्ति ने कई दिनों तक तो ध्यान नहीं दिया, पर आखिरकार उससे रहा न गया और उसने ऐसा करने का कारण पूछ ही लिया. वृद्ध ने कहा- नदी पार जाने में समय लगता है, इसलिए सोचा, क्यों न नदी में रेत डालकर पार जाने के लिए बांध बना लूं. यवकीर्ति हंसने लगा. उसने कहा- भगवान हर काम का एक तरीका होता है. उसकी निश्चित प्रक्रिया होती है. आप पार जाने के लिए दूसरे संभव तरीके अपनाएं और इस बाल क्रीड़ा को छोड़ दें. इस पर ब्राम्हण ने कहा- ठीक कहा आपने. इसी तरह ज्ञान प्राप्त करने की भी निश्चित प्रक्रिया होती है, यवकीर्ति को बात समझ में आ गई.

नेटीजन

हिमालय की मान्यताएं

उत्तराखंड, हिमाचल, चित्राल, बाल्टिस्तान, तिब्बत व नेपाल का आध्यात्मिक इतिहास एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है. यहां पहाड़ों की जोगणियां वास्तव में योगिनियों से अलग शक्तियां हैं.

उत्तराखंड के टिहरी जिले में थात गांव से ऊपर चढ़ाई पर ₹खैटखाल' नाम से एक मंदिर है. इसके विषय में अभी एक न्यूज चैनल पर दिखाया गया. मुझे लगता है कि आधी-अधूरी जानकारी के आधार पर ऐसे एपिसोड बनाने का जोर है. खैट पर्वत यहां आने-जाने वाली अप्सराओं के लिए प्रसिद्ध है. हिमाचल में हम इन शक्तियों को ₹जोगणियां' कहते हैं. जहां तक मैंने इनके बारे में पढ़ा-जाना है, यहां पहाड़ों की जोगणियां वास्तव में योगिनियों से अलग शक्तियां हैं. खैट पर्वत की अप्सराएं और हिमाचल के शिखरों पर स्थित शक्तियां एक ही स्वरूप वाली हैं. उत्तराखंड, हिमाचल, चित्राल, बाल्टिस्तान, तिब्बत व नेपाल का आध्यात्मिक इतिहास एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है. उत्तराखंड में अप्सराओं के लिए प्रयुक्त होने वाला स्थानीय शब्द है ₹आछरी', जो हिमालय की प्राचीन ₹किराती' बोली का शब्द है. हमारे यहां भेखली धार से ऊपर पहाड़ी की चोटी पर स्थित हमारी अधिष्ठाता जोगणी -फुंगणी माता को भी ₹आछरी' कहा जाता है. इस शक्ति का पूरा नाम ₹लोहड़ी आछरी' है, जिनका बाकायदा एक रथ बना हुआ है. लाहौलस्पीति में इन्ही अप्सराओं की शक्तियों को खांडरुम कहते हैं. इसलिए संशय नहीं कि खैटखाल की शक्तियां भी किराती समुदाय की पूजनीय अप्सराएं व यक्षणियां हैं.

यतिन पंडित की फेसबुक वॉल से.

पाकिस्तान

मुद्दे जो हावी रहेंगे

चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि इस बार सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले युवा सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे.चुनाव मे भ्रष्टाचार और गिरती अर्थव्यवस्था बड़ा मुद्दा रहेगा.

पाकिस्तान में आम चुनाव 25 जुलाई को होने जा रहे हैं. संसद व चारों प्रांतों की असेंबलियों के चुनाव उसी दिन होंगे. इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज पार्टी और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ जरदारी की पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी पार्लिया-मेंटेरियन्स के बीच त्रिपक्षीय मुकाबला होगा. भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होगा. दूसरा मुद्दा पाक की दिन ब दिन खराब होती अर्थव्यवस्था है. बेरोजगारी चरम पर है. प्रांतों के साथ मतभेदी व्यवहार भी एक बड़ा मुद्दा है. देश में पंजाब प्रांत का दबदबा है. पंजाब को बांटकर सरायकी और भावहलपुर प्रांत बनाने की मांग जारी है. इमरान खान खुद को नवाज शरीफ के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं. शरीफ अदालत द्वारा अयोग्य ठहराए जाने से खुद चुनाव नहीं लड़ सकते. इमरान अपनी पार्टी में अपराधियों, इस्लामिक चरमपंथियों, बलात्कारियों और डाकुओं की मौजूदगी से मुश्किल में हैं. उनके चरित्र पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है. अपनी तीन पत्नियों को तलाक दे चुके हैं. उनकी पत्नी रेहम खान की किताब ₹टेलऑल' के लीक हुए कुछ अंशों ने तहलका मचा रखा है. रेहम खान ने यह भी कहा है कि इमरान इस धरती पर सबसे गंदा इंसान है. कुछ अरसे से पाकिस्तान में ₹पख्तून तहफ्फुज आंदोलन' चल रहा है. राजनेता इसका विरोध नहीं कर पा रहे क्योंकि ऐसा किया तो पख्तूनों का वोट नहीं मिल पाएगा. पख्तून राष्ट्रवादी पाक सेना और आईएसआई से इसलिए नाराज हैं कि सेना द्वारा कबाईली क्षेत्र में हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के खात्मे के लिए बमबारी में उनके हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी. आसिफ अली जरदारी की पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे. नवाज शरीफ इन दिनों फौज, आईएसआई के घेरे में फंसे हुए हैं. मुख्य कारण है उनका वह बयान जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान से जाकर आंतकवादियों ने 2008 में मुंबई में 150 निर्दोष लोगों की जान ले ली और उनका यह पूछना कि आखिर, उनके खिलाफ ट्रायल क्यों नहीं पूरा करते.

लोग नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ के समर्थन में आगे आ रहे हैं. समझने लगे हैं कि अदालत ने शरीफ को पार्टी के मुखिया और प्रधानमंत्री के पद से सेना के इशारे पर हटाया है. चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है ताकि शरीफ राजनीति से ताउम्र के लिए बाहर हो जाएं. माना जा रहा है कि पाक सेना सब पर भारी है. इसलिए चुनाव में जीत पाक सेना और आईएसआई के दबाव पर तय होगी. बहरहाल, चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि इस बार सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले युवा सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे. मतदाता, जिनमें युवा मतदाता ज्यादा हैं, न सिर्फ ऑनलाइन प्रचार के उपकरणों का इस्तेमाल कर मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि चुनाव के दिन बड़ी संख्या में मताधिकार का इस्तेमाल कर चुनावी तस्वीर को भी बदल सकते हैं. **कुलदीप तलवार.**

आपकी बात

घर स्वर्ग..घर ही नर्क

नियति भी क्या-क्या खेल दिखाती है. जो दूसरों को जीने के लिये प्रेरित करते थे, वही भय्युजी महाराज अपने ही पारिवारिक कलह का वार नहीं सह सके, और आत्महत्या कर ली. गरीबों और असहायों का जीवन संवारने वाले भय्युजी अपने ही घर में असहाय हो गये. खबरों पर चील की तरह झपटने वाला मीडिया उनके घर की बातों को मुर्दा मांस की तरह उधेड़ता रहने वाला है.

बात अपने घरों की करें. संयुक्त परिवारों की तो बात ही दूर, अब तो जितने छोटे टुकड़ों में टूट सकता है परिवार टूटता जा रहा है. और इस टूटन के बीच जुड़ाव जैसा कुछ नजर नहीं आता. घर-घर की कलह आमबात हो गयी है.

प्रेम के दीवाने जितनी आसानी से शादी कर लेते हैं, उस शादी को टूटने में भी समय नहीं लगता. आज की दुनिया सिर्फ पैसों की दुनिया रह गयी है. अपने ही स्वास्थ की कीमत पर जब पैसा कमाया जा रहा है, तो दूसरों की बात ही क्या.

दूसरी तरफ ₹जनरेशन गैप' के कारण बड़े-बूढ़ों की दुर्गत तो हो ही रही है. लगता है जैसे परिवार का हर सदस्य अलग-अलग किनारों पर खड़ा है. समस्या तो नजर आती है, हलाहीं.

एम.एन. भाटिया, अमरावती.

'अगर' भविष्यवाणी

अगर लोकसभा-2019 के चुनाव में विपक्षी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ती हैं, बहुमत से विजयी होती हैं, तो राहुल गांधी निश्चित ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं.

लेकिन राहुल गांधी को जल्दबाजी न दिखाकर फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा. यह भी हो सकता है कि विपक्षियों द्वारा जीत दर्ज करने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस सुप्रीमो शरद पवार भी प्रधानमंत्री पद के लिये अपनी दावेदारी पेश कर दें. पवार राजनीति के पुराने और मंजे हुए खिलाड़ी हैं. लगता नहीं कि वे राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार करेंगे. अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी को उप-प्रधानमंत्री पद लेना पड़ सकता है. लेकिन इसमें दो राय नहीं कि राहुल गांधी ने अब अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है.

जगदीश सुदा, अमरावती.

सुविचार

जब मैं इस संसार से बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला. जब मैंने अपने मन में झाँक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है.

संत कबीर.

प्रतिदिन अखबार

यह पत्र मालिक, प्रकाशक, सम्पादक नानक आहूजा द्वारा देविका वेब प्रिंटर्स, राजापेठ, अमरावती से मुद्रित कर 'प्रतिदिन अखबार' कार्यालय, देविका परिसर, ब्राह्मण सभा के पीछे, दरोगा प्लॉट, राजापेठ, अमरावती 444 606 से प्रकाशित किया है. फोन-0721-2560155/56/57/58 फैक्स-0721-2677708 E-mail :- pratidinnews@gmail.com
'प्रतिदिन अखबार' में प्रकाशित होनेवाले विभिन्न लेख, पत्र, साहित्य, लेखकों, कवियों आदि के विचारों या तथ्यों पर आधारित होते हैं. इन लेखकों के विचारों अथवा तथ्यों से संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है. संपादक पर मात्र सम्पादकीय लेखों का ही दायित्व है. संपादक-नानक आहूजा, समाचार संपादक-प्रवीण आहूजा.